रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012/वैशाख 12, 1934

No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2012/VAISAKHA 12, 1934

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सं. 15/1/2008-पारेषण (खंड-III).—पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश ।

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 13-4-2006 के संकल्प संख्या 11/30/2004-पीजी/पारेषण के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे तथा इन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत 4-7-2007 और 10-10-2008 को संशोधित किया गया था ।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किया जाता है ।

राज्य पारेषण परियोजनाएं — पैरा 24 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :—

"जहां तक अंत:राज्यीय परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं और राज्य में पारेषण परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसी प्रकार की समितियों का गठन कर सकती हैं । राज्यों के पास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत अपने राज्यों में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए योजना आयोग के वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) आधारित माडल ट्रांसमिशन एग्रीमेंट (एमटीए) दस्तावेज के उपयोग का विकल्प भी है ।"

ए. के. सक्सेना, निदेशक

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd May, 2012

No. 15/1/2008-Trans (Vol.-III).—Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects.

The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified vide Resolution No. 11/30/2004-PG/Trans, dated 13-4-2006 and were amended on 4-7-2007 and 10-10-2008 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following further amendment is hereby made in the above guidelines.

State Transmission Projects — Para 24 has been substituted by the following :—

"As far as Intra-State projects are concerned, the State Governments may adopt these guidelines and may constitute similar committees for facilitation of transmission projects within the State. The States also have the option to use Viability Gap Funding (VGF) based Model Transmission Agreement (MTA) document of Planning Commission for development of Transmission System in their States under Public Private Partnership (PPP) mode."

A.K. SAXENA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.